सत्यमेव जयते

आउटकम बजट 2021-22 की स्टेटस रिपोर्ट

31 दिसम्बर **2021** तक

योजना विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

मार्च 2022

विषय सूची

क्र सं	विभाग	पृष्ठ संख्या
I.	भूमिका	01
II.	शिक्षा निदेशालय	05
III.	उच्च शिक्षा निदेशालय	07
IV.	प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा निदेशालय	09
V.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	11
VI.	समाज कल्याण विभाग	13
VII.	महिला ओर बाल विकास विभाग	14
VIII.	अजा/अजजा/अपिव कल्याण विभाग	15
IX.	खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग	16
X.	शहरी विकास विभाग और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड	17
XI.	दिल्ली जल बोर्ड	19
XII.	परिवहन विभाग	21
XIII.	लोक निर्माण विभाग (सड़क और पुल)	23
XIV.	विद्युत् विभाग	25
XV.	पर्यावरण और वन विभाग	27
XVI.	प्रशासनिक सुधार विभाग	29
XVII.	आउटकम बजट से सीख और आगे का रास्ता	30

I. भूमिका

माननीय अध्यक्ष महोदय,

1. मैं सदन के समक्ष अपनी सरकार का लगातार पांचवा रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते हुए गर्व की अनुभूति कर रहा हूं। इसमें आउटकम बजट 2021-22 के तहत दिसंबर 2021 तक योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं की प्रगति और उपलब्धियों का विवरण है।

2. जैसा कि आप सभी को अवगत हैं दिल्ली का आउटकम बजट एक अनूठा दस्तावेज़ है जिसने सार्वजनिक धन के उपयोग में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाये रखने में महत्वपूर्ण वृद्धि की है। बजट आवंटन अब न केवल वित्तीय उपलब्धियों में मापा जाता है बल्कि यह स्पष्ट रूप से मापन योग्य आउटपुट और आउटकम संकेतकों में भी विभाजित है जिनका निरीक्षण बड़ी आसानी से किया जा सकता है।

3. 2021-22 के आउटकम बजट दस्तावेज को व्यापक रूप से संशोधित किया गया है ताकि इसमें विभागों के लक्ष्य शामिल किये जा सकें और इन्हें आउटकम बजट संकेतकों के साथ मापा जा सके। आउटकम बजट 2021-22 में अनेक संकेतक हैं जिनमें उपलब्धियों का मापन योजनाओं से लाभान्वित लोगों के संतोष स्तर के आधार पर किया जायेगा, जिसकी जानकारी विभागों से उपलब्ध प्रशासनिक आंकड़ों से नहीं बल्कि सर्वेक्षणों से प्राप्त वास्तविक तथ्यों से मापी जाएगी। वर्ष 2021-22 में हमने स्वास्थ्य विभाग के ऐसे अनेक संकेतकों का सर्वेक्षण कराया था और उनसे उपलब्ध आंकड़े इस परिपत्र में शामिल किये गये हैं।

4. आउटकम बजट दिल्ली सरकार की प्रत्येक प्रमुख योजना और कार्यक्रम के प्रदर्शन को दो प्रकार के संकेतकों में विभाजित करता है:

(i) "आउटपुट" का तात्पर्य किसी परियोजना या कार्यक्रम के परिणामस्वरूप उपलब्ध करायी गयी मूर्त बुनियादी व्यवस्था या सेवा से है, जैसे मोहल्ला क्लीनिक बनाना, शौचालयों का निर्माण, कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का संचालन आदि।

(ii) "आउटकम" उस सीमा को दर्शाता है जहां तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के लोग एक लघु अवधि में सार्वजनिक आधारभूत संरचना या प्रदत्त सेवाओं से कितने लाभान्वित हुए हैं। इन्हें समझना और इनपर नजर रखना महत्वपूर्ण है क्योंकि आउटपुट की केवल उपस्थिति या आपूर्ति ही, सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता और नागरिकों के लाभान्वित होने की सीमा का आश्वासन नहीं है। बल्कि इन आउटकम की सफल सुपुर्दगी ही किसी भी सरकारी योजना के दीर्घावधि लक्ष्यों को पूरा करेगी जैसे कि बेहतर शैक्षणिक परिणाम, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, खुले में शौच से मुक्त शहर, रोजगार अवसरों में बढोतरी इत्यादि।

5. मैं "आउटकम बजट 2021-22 की स्टेटस रिपोर्ट" प्रस्तुत करना चाहूंगा, दूसरे शब्दों में कहा जाय तो यह इस बात का रिपोर्ट कार्ड है कि विभिन्न विभागों ने वार्षिक बजट 2021-22 के तहत आवंटित निधि का किस तरह उपयोग किया है। यह रिपोर्ट कार्ड इस बात की जानकारी देता है कि क्या राशि का उपयोग उस उद्देश्य के लिये हुआ जिसके लिये यह दी गयी थी। साथ ही यह निधि के उपयोग का आउटकम और 31 दिसंबर 2021 तक आउटकम और आउटपुट संकेतकों के आधार पर एक विभाग के कुल प्राप्तांको की प्रतिशत के रूप में जानकारी भी है।

6. माननीय अध्यक्ष महोदय वित्तीय वर्ष 2021-22 की शुरुआत अप्रैल -मई 2021 में कोविड महामारी की दूसरी घातक लहर के साथ हुई थी और तीसरी लहर ने भी स्वास्थ्य देखभाल संबंधी बुनियादी ढांचे पर भारी दबाव डाला और लॉकडाउन/प्रतिबंधो ने सामाजिक - आर्थिक गतिविधियों को लगभग ठप्प कर दिया। हमारी सरकार ने महामारी का डटकर मुकाबला किया फिर भी इससे सरकार की नियमित गतिविधियों में भारी व्यवधान आया। कोविड-19 के घातक असर को कम से कम करने के लिये सरकारी संसाधनो और प्रयासों को लक्षित किया गया था । लॉकडाउन से आउटकम बजट 2021-22 में तय लक्ष्यों की प्रगति और उपलब्धियों पर असर पड़ा।

7. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अब वर्तमान वित्तीय वर्ष के आउटकम बजट की मुख्य उपलब्धियों को प्रस्तुत करना चाहूंगा।

स्वास्थ्य

8. दिल्ली सरकार ने अपने अस्पतालों, औषधालयों और आम आदमी मोहल्ला क्लीनिकों में 330 परीक्षण लैब/केंद्र स्थापित किये हैं। 31 दिसंबर 2021 तक 3.28 करोड़ परीक्षण कराये गये। इनमें से 14.51 लाख लोग संक्रमित पाये गये।

9. 2 मार्च 2022 तक 1.73 करोड़ लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज, 1.37 करोड़ को दूसरी डोज लगा दी गयी और 15-17 वर्ष आयुवर्ग के 15,21,535 लाभार्थियों को भी टीके लगाये गये।

10. महोदय, दिल्ली सरकार ने संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कोविड बिस्तरों की संख्या में भारी वृद्धि कर अस्पतालों की बुनियादी ढांचा व्यवस्था में समय से बढोतरी सुनिश्चित की और कोविड मौतों पर अंकुश लगाया। दिल्ली सरकार ने 15.02.2022 तक सरकारी और निजी स्वास्थ्य केंद्रों सहित कोविड देखभाल केंद्रों में 3,626 बिस्तर, कोविड स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में 198 बिस्तर और समर्पित कोविड अस्पतालों में 15,357 बिस्तरों की उपलब्धता सुनिश्चित की।

शिक्षा निदेशालय

11. कोविड महामारी के दौरान विद्यार्थियों की सुविधा के लिये प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाईन सुनिश्चित की गयी ताकि वे स्कूल गये बिना दाखिला ले सकें। इससे प्रवेश प्रक्रिया सरल हुई तथा माता-पिता और अभिभावकों की कठिनाई भी दूर हुई।

12. 2021-22 के दौरान लगभग 2,300 विद्यार्थियों के साथ एसटीईएम, मानव विज्ञान, प्रदर्शन और दृश्य कला तथा 21 वी सदी के अत्याधुनिक कौशल के कार्यक्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त उत्कृष्ट विद्यालय आरंभ किये गये। रुचि आधारित ये विद्यालय कक्षा 9 से 12 के लिये हैं।

13. बिजनेस ब्लास्टर परियोजना के तहत लगभग 3 लाख विद्यार्थियों को 2,000 रुपये प्रति विद्यार्थी की दर से सीड मनी उपलब्ध करायी गयी ताकि वे अपने नये विचारों के साथ व्यवसाय शुरू कर सकें।

खाद्य और नागरिक आपूर्ति

14. दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन कार्ड धारकों और जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे, जिनमें बड़ी संख्या प्रवासी कामगारों की थी, दोनों वर्गों को निशुल्क सूखा राशन उपलब्ध कराया। अप्रैल से लेकर दिसंबर 2021 तक कुल 68.94 लाख मौजूदा कार्ड धारकों को निशुल्क राशन मिला। इसके अतिरिक्त 31.76 लाख ऐसे लोगों को भी निशुल्क राशन मिला जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे।

विद्दुत विभाग

15. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक, लोड पर ध्यान दिये बगैर, 200 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली उपभोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली और 201 यूनिट से 400 यूनिट प्रतिमाह बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को बिजली बिल में 800 रुपये तक की छूट उपलब्ध करायी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में न्यायालय परिसरों में वकील चैम्बर को भी सब्सिडी का लाभ दिया गया। वित्तीय वर्ष 2021-22 में दिल्ली में कहीं भी रह रहे 1984 के सिख दंगा पीड़ित परिवारों को प्रतिमाह 400 यूनिट तक की खपत पर शत प्रतिशत बिजली सब्सिडी दी गयी।

16. दिल्ली ने अप्रैल - दिसंबर 2021 के दौरान 7323 मेगावाट की पीक मांग को सफलता पूर्वक पूरा किया।

अनुसूचित जाति/जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

17. जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना के अंतर्गत 31 दिसंबर 2021 तक 46 कोचिंग संस्थान सूचीबद्ध किये गये और 2021-22 के दौरान 12,600 विद्यार्थी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा पाठ्यक्रमों के लिये नामांकित किये गये।

18. इन नामांकित विद्यार्थियों और पिछले वर्ष की प्रवेश परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों में से 1,029 ने इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा में क्वालिफाई किया जबकि 245 विद्यार्थियों ने एसएससी, अध्यापन, बैंकिंग, लिपिक वर्ग, पुलिस इत्यादि विविध परीक्षाओं में क्वालिफाई किया।

परिवहन

19. परिवहन विभाग ने सभी सार्वजनिक सेवायें को फेसलेस (बिना विभाग आए सारी सुविधाएं पाएं) तरीके से उपलब्ध कराने की बड़ी पहल की है। इस कार्यक्रम मे दिसंबर 2021 तक लगभग 5 लाख आवेदक लाभान्वित हुए। मैं सम्मानित सदन को यह भी बताना चाहूंगा कि विद्युत वाहन नीति लागू होने के बाद से दिल्ली में 31,105 विद्युत वाहन पंजीकृत हो चुके हैं।

20. महोदय, हमारी सरकार ने एकबार फिर 1.78 लाख लोगों को एक मुश्त 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी है। कोविड की कठिनाईयां कम करने के लिये यह सहायता दिल्ली में सार्वजनिक वाहन सेवा बैज के साथ वैध ड्राइविंग लाइसेंस धारकों, पैरा ट्रांजिट वाहन (ऑटो रिक्शा, टैक्सी, ग्रामीण सेवा, फटफट सेवा, मैक्सी कैब, पर्यावरण अनुकूल सेवा, ई-रिक्शॉ और स्कूल कैब इत्यादि) के परमिट धारकों और ई रिक्शॉ मालिकों को दी गयी।

लोक निर्माण विभाग

21. यह बताने में मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है कि सरकार ने आजादी के 75 वर्ष के उपलक्ष में जनवरी 2022 तक 75 स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया है और दिल्ली के आकाश को तिरंगे से सुशोभित किया है।

22. महोदय मैं अब प्रमुख विभागों के संदर्भ में आउटकम बजट 2021-22 की स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करना चाहूंगा।

II. शिक्षा निदेशालय

(I) 2021-22 के आउटकम बजट में 36 कार्यक्रम/स्कीम शामिल की गई थीं जिनमें 104 आउटपुट /आउटकम संकेतक थे। विभाग के आउटपुट और आउटकम संकेतों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

क	संकेतकों की कुल सख्या	104
ख	"लागू नहीं" संकेतकों की कुल संख्या	44
ग	मूल्यांकन के लिए संकेतकों की संख्या (क-ख)	60
i	संकेतकों की संख्या – "ऑन ट्रैक"	43 (72%)
ii	संकेतकों की संख्या– "ऑफ ट्रैक"	17 (28%)

(ii) प्रगति दर्शाने वाला पाई चार्ट

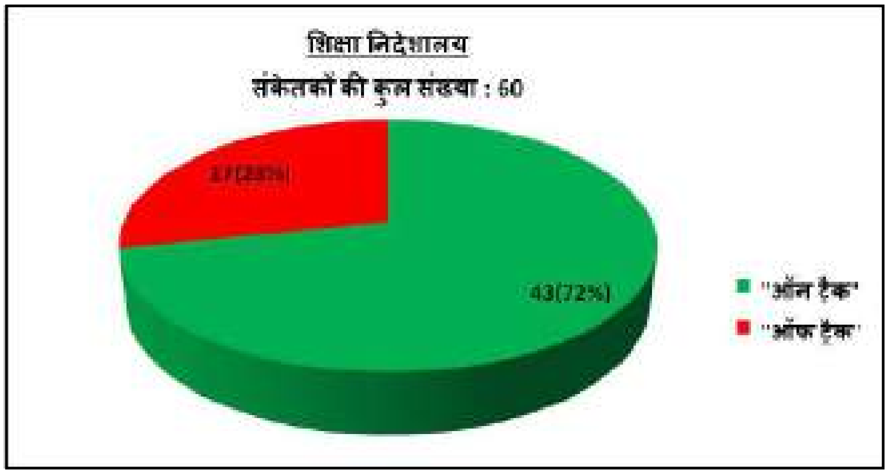

(iii) प्रमुख संकेतकों की स्थिति (दिसम्बर 2021 तक)

- फरवरी 2022 तक दिल्ली सरकार द्वारा 13,181 नई कक्षाओं का निर्माण एवं संचालन किया गया है।
- 2021-22 में सरकारी स्कूलों में नामांकन 17.79 लाख छात्रों तक पहुंच गया।
- एससीईआरटी ने दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार के 31,539 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जबकि वार्षिक लक्ष्य 42,989 शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का था।
- बिजनेस ब्लास्टर प्रोजेक्ट के अंतर्गत करीब तीन लाख विद्यार्थियों को प्रति छात्र 2,000 हजार रुपये

की सीड मनी प्रदान की गई, ताकि वे नये व्यावसायिक विचार सामने लाएं और उन्हें लागू करें।

- दिल्ली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (डीबीएसई) की स्थापना कर दी गयी है और बोर्ड ने दिल्ली सरकार के 30 स्कूलों के साथ काम करना शुरू कर दिया है।
- वर्ष 2021-22 के दौरान, विशेषज्ञता क्षेत्रों में उत्कृष्ट विद्यालय पहल (एसओएसई) के अंतर्गत 20 स्कूलों ने करीब 2,300 विद्यार्थियों के साथ एसटीईएम, मानविकी, अभिनय और दृश्य कलाओं जैसे क्षेत्रों तथा 21वीं सदी के उच्च कोटि के कौशलों में पाठ्यक्रम शुरू किए। पसंद-आधारित ये विद्यालय 9वीं से 12वीं कक्षा तक हैं।
- शिक्षा का अधिकार-आरटीई के अतंर्गत 38,684 विद्यार्थियों को दाखिला देने के वार्षिक लक्ष्य (2021-22) की दिशा में 25,327 विद्यार्थियों ने दाखिला लिया।
- 728 स्कूल भवनों में से, 577 भवनों में सीसीटीवी कैमरा लगाए गए।
- 26,346 के वार्षिक लक्ष्य के संदर्भ में आउट ऑफ स्कूल 25,152 विद्यार्थियों को विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों (एसटीसीज) में दाखिला दिया गया है।
- विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए दिल्ली सरकार द्वारा कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को मार्ग-दर्शन प्रदान करने के वास्ते देश का मेंटर कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 99,610 छात्रों को 49,203 मेंटरो से जोड़ा गया।
- दिल्ली सरकार के सभी स्कूलों में बारहवीं कक्षा तक के सभी छात्रों के लिए 28 सितम्बर 2021 को देशभक्ति पाठ्क्रम का शुभारंभ किया गया।

III. उच्च शिक्षा निदेशालय

(I) 2021-22 के आउटकम बजट में 22 कार्यक्रम/स्कीम शामिल की गईं, जिनमें 73 आउटपुट/आउटकम संकेतक तय किए गए थे। विभाग के आउटपुट और आउटकम संकेतकों का ब्यौरा नीचे दिया गया है: -

क	संकेतकों की कुल सख्या	73
ख	"लागू नहीं" संकेतकों की कुल संख्या	19
ग	मूल्यांकन के लिए संकेतकों की संख्या (क-ख)	54
i	संकेतकों की संख्या – "ऑन ट्रैक"	34 (63%)
ii	संकेतकों की संख्या– "ऑफ ट्रैक"	20 (37%)

(ii) प्रगति दर्शाने वाला पाई चार्ट

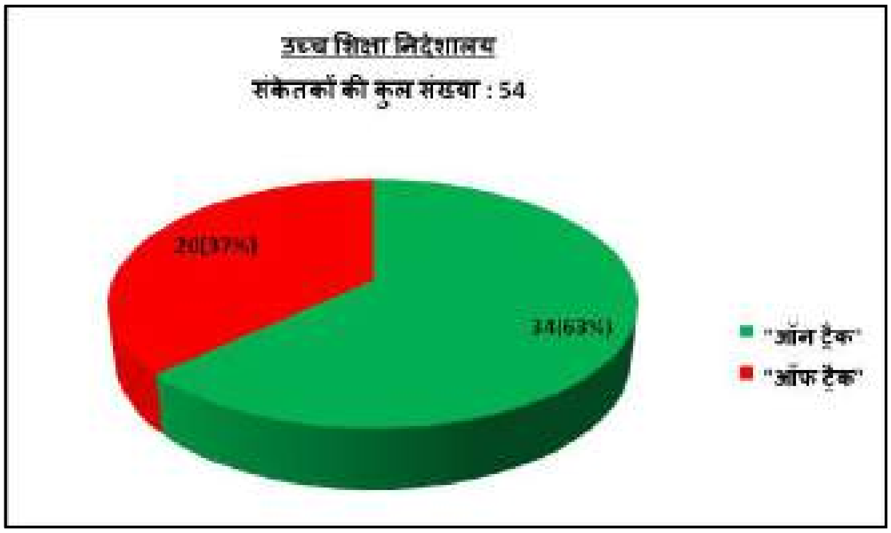

(ii) प्रमुख संकेतकों की स्थिति (दिसम्बर 2021 तक)

- सूरजमल विहार में गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (जीजीएसआईपीयू) का नया पूर्वी परिसर - परियोजना में 95% काम पूरा हो चुका है। परियोजना के 2022 में पूरा होने की संभावना है।
- दिल्ली खेल विश्वविद्यालय: खेल विश्वविद्यालय अधिनियम को शासकीय राजपत्र में अधिसूचित किया गया है। दिल्ली के हिरनकूदना (मुंडका के पास) गांव में लगभग 80 एकड़ जमीन को

माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के अनुमोदन के बाद उच्च शिक्षा निदेशालय को स्थानांतरित कर दिया गया है। वर्तमान में, दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी लुडलो कैसल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में काम कर रही है।

- दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय: - मंत्रिपरिषद ने दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय विधेयक के मसौदे के कैबिनेट नोट को मंजूरी दी थी और उसे जनवरी 2022 में दिल्ली विधानसभा द्वारा पारित कर दिया गया। तदनुसार, दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय अधिनियम 2022 को 10.01.2022 को अधिसूचित किया गया है। विश्वविद्यालय का स्थायी परिसर दिल्ली के बक्करवाला गांव में लगभग 12 एकड़ भूमि पर स्थापित किया जाना है।
- शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय की "योग्यता एवं अर्थोपाय" से जुड़ी वित्तीय सहायता योजना" के तहत 6820 विद्यार्थियों को 48.14 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई जबकि 2019-20 के दौरान 3760 छात्रों को 24.01 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी।

IV. प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा निदेशालय

(I) आउटकम बजट 2021-22 में 13 कार्यक्रमों/योजनाओं को शामिल किया गया था जिनमें 60 आउटपुट/आउटकम संकेतक तय किए गए थे। विभाग के आउटपुट और आउटकम संकेतकों का विवरण इस प्रकार है: -

क	संकेतकों की कुल सख्या	60
ख	"लागू नहीं" संकेतकों की कुल संख्या	12
ग	मूल्यांकन के लिए संकेतकों की संख्या (क-ख)	48
i	संकेतकों की संख्या – "ऑन ट्रैक"	37 (77%)
ii	संकेतकों की संख्या– "ऑफ ट्रैक"	11 (23%)

(ii) प्रगति दर्शाने वाला पाई चार्ट:

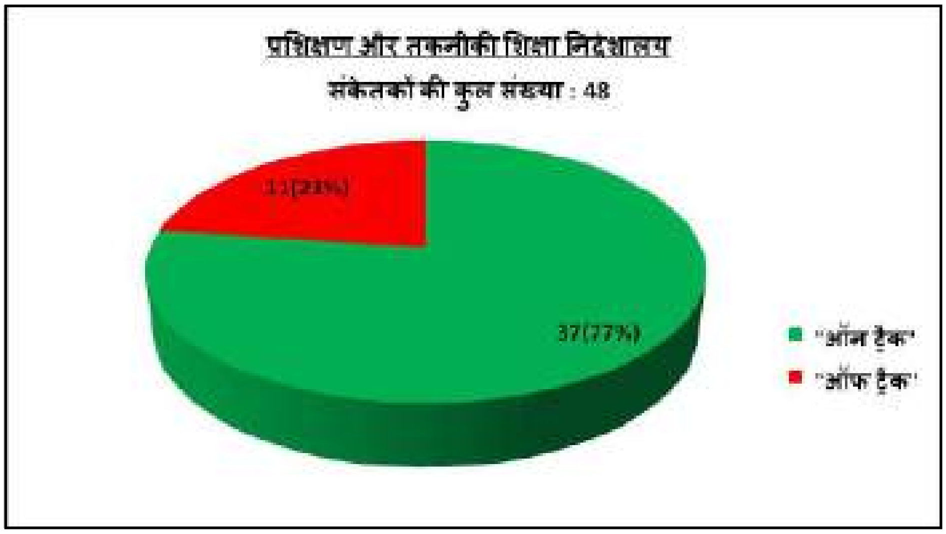

(ii) प्रमुख संकेतकों की स्थिति (दिसम्बर 2021 तक)

- शैक्षणिक सत्र 2021-22 में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में सीटों की संख्या 2020-21 में 10,030 से बढ़कर 2021-22 में 17,396 हो गई है।
- आईटीआई में, 2020-21 में 9,589 छात्रों के मुकाबले 2021-22 में 10,165 छात्रों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया गया।

- दिल्ली सरकार के तकनीकी शिक्षा संस्थानों द्वारा 31 दिसंबर, 2021 तक कुल 84 पीएचडी डिग्री प्रदान की गई, जबकि वार्षिक लक्ष्य 114 पीएचडी डिग्री करने का है।
- शिक्षा के विभिन्न विषयों में कौशल शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी (डीएसईयू) की स्थापना की गई है, जिसने 15 अगस्त, 2020 से काम करना शुरू कर दिया था। 52 पाठ्यक्रमों के निर्धारित वार्षिक लक्ष्य की तुलना में 39 पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं और दिसंबर 2021 तक कुल सीटों का 94.5% सीटें भरी जा चुकी थीं।
- रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार की एक पहल के अंतर्गत "ध्यान एवं योग विज्ञान केन्द्र यानी सेंटर फॉर मेडिटेशन एंड योग साइंसेज" ने दिल्ली फार्मास्युटिकल साइंसेज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी (डीपीएसआरयू) परिसर में काम करना शुरू दिया है। 450 प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित और प्रमाणित किया गया है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 31 दिसंबर, 2021 तक 80 शिविरों में (प्रत्येक शिविर में 25) लगभग 2,000 नागरिक लाभान्वित हुए हैं।
- दिल्ली सरकार के तकनीकी शिक्षा विश्वविद्यालयों और संस्थानों के संकायों द्वारा 31 दिसंबर, 2021 तक कुल 1,670 शोध आलेख प्रकाशित किए गए, जबकि 2020-21 में 1,960 शोध आलेख प्रकाशित किए गए।
- दिल्ली सरकार के तकनीकी विश्वविद्यालयों में, छात्रों ने दिसंबर, 2021 तक 284 कार्यशालाओं में भाग लिया जबकि 2020-21 में 212 कार्यशालाओं में भाग लिया था।

V. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

(I) आउटकम बजट 2021-22 में 23 कार्यक्रमों/योजनाओं को शामिल किया गया था जिनमें 121 आउटकम/आउटपुट संकेतक तय किए गए थे। विभाग के आउटकम और आउटपुट संकेतकों का विवरण इस प्रकार है:-

क	संकेतकों की कुल सख्या	121
ख	"लागू नहीं" संकेतकों की कुल संख्या	11
ग	मूल्यांकन के लिए संकेतकों की संख्या (क-ख)	110
i	संकेतकों की संख्या – "ऑन ट्रैक"	81 (74%)
ii	संकेतकों की संख्या– "ऑफ ट्रैक"	29 (26%)

(ii) प्रगति दर्शाने वाला पाई चार्ट

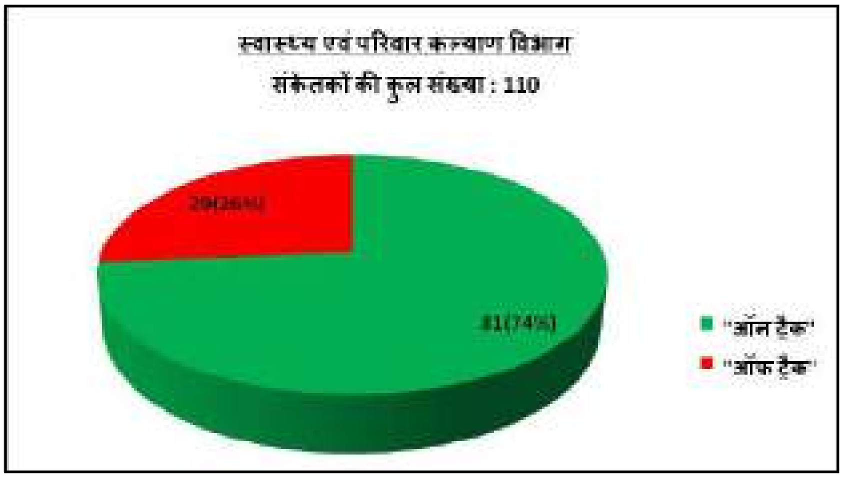

(ii) प्रमुख संकेतकों की स्थिति (दिसम्बर 2021 तक)

- 1000 आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक (एएएमसी) के लक्ष्य की दिशा में 31 दिसंबर 2021 को समाप्त नौ महीने की अवधि में कुल 520 आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक चालू किए गए जिनमें 1.44 करोड़ रोगियों का इलाज किया गया। प्रत्येक आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक में प्रतिदिन औसतन, 116 रोगी आते हैं।
- आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से 90% से अधिक रोगी संतुष्ट हैं।
- मोहल्ला क्लीनिक में 85% से अधिक रोगियों ने डॉक्टर से मिलने के लिए 20 मिनट से भी कम

समय तक प्रतीक्षा की।

- 3.01 लाख बच्चों के वार्षिक लक्ष्य की तुलना में 9-11 माह आयु वर्ग के लगभग 2.26 लाख बच्चों का पूर्ण टीकाकरण किया गया।
- 2.25 लाख संस्थागत प्रसव के वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले दिसंबर 2021 तक आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से 1.58 लाख संस्थागत प्रसव की सुविधा प्रदान की गई।
- दिसंबर 2021 तक 74,782 टीबी रोगियों का इलाज किया गया, जबकि 2020-21 में कुल 88,127 रोगियों का उपचार किया गया था।
- औषधि नियंत्रण विभाग ने करीब 3800 दवा विक्रेता केन्द्रों का निरीक्षण किया और मानदंडों का उल्लंघन करने वाली फर्मों में से दिसंबर 2021 तक 664 लाइसेंस निलंबित या रद्द कर दिए।
- दिल्ली सरकार के सभी सरकारी अस्पतालों में 13844 बेड उपलब्ध है।
- आउटकम बजट के अनुसार अप्रैल 2021 से दिसंबर 2021 की अवधि में दिल्ली सरकार के 38 अस्पतालों में (ओपीडी, आईपीडी और कैजुअल्टी के अंतर्गत) लगभग 2 करोड़ रोगियों ने स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का लाभ उठाया।
- एकीकृत परामर्श और परीक्षण केंद्रों (आईसीटीसीएस) में 35,1121 लोगों की एचआईवी जांच की गई।
- एचआईवी प्रभावित/ संक्रमित और दोहरे अनाथ बच्चों के लिए दिल्ली राज्य एड्स नियंत्रण समिति की वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत दिसम्बर 2021 तक एचआईवी ग्रसित/ प्रभावित 5501 व्यक्तियों को दिल्ली सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है।
- दिल्ली आरोग्य कोष (डीएके) व्यय प्रतिपूर्ति योजना के तहत अप्रैल 2021 से दिसंबर 2021 की अवधि में 2804 लोगों ने प्राईवेट अस्पतालों से कैशलैस उपचार (दुर्घटना, एसिड अटैक, थर्मल बर्न और चोट जैसे मामलों में) की सुविधा प्राप्त की और निजी केंद्रों पर 71,559 रेडियोलॉजिकल परीक्षण की अनुशंसा की गई।
- दिसंबर 2021 तक 100 % पात्र लोगों को कोविड-19 टीके की पहली डोज दी गई और 73 % पात्र लोगों को कोविड-19 टीके की दोनों डोज दी गई।

VI. समाज कल्याण विभाग

(I) आउटकम बजट 2021-22 में 8 कार्यक्रमों/योजनाओं को शामिल किया गया था जिनमें 40 आउटपुट/आउटकम संकेतक तय किए गए थे। विभाग के आउटपुट और आउटकम संकेतकों का विवरण इस प्रकार है:-

क	संकेतकों की कुल सख्या	40
ख	"लागू नहीं" संकेतकों की कुल संख्या	7
ग	मूल्यांकन के लिए संकेतकों की संख्या (क-ख)	33
i	संकेतकों की संख्या – "ऑन ट्रैक"	18 (55%)
ii	संकेतकों की संख्या– "ऑफ ट्रैक"	15 (45%)

(ii) प्रगति दर्शाने वाला पाई चार्ट

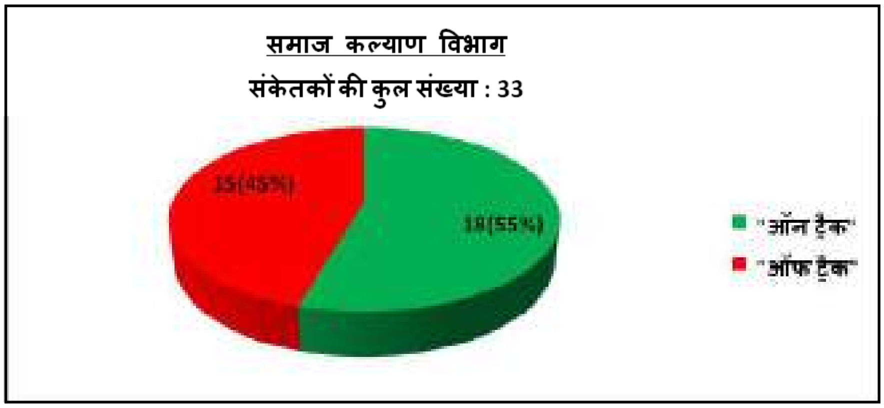

(ii) प्रमुख संकेतकों की स्थिति (दिसम्बर 2021 तक)

- वर्ष 2020-21 में लगभग 4.02 लाख वरिष्ठ नागरिकों की तुलना में वर्ष 2021-22 में लगभग 4.29 लाख वरिष्ठ नागरिकों को मासिक वित्तीय सहायता दी गई है।
- वर्ष 2020-21 में 98,064 व्यक्तियों की तुलना में वर्ष 2021-22 में 1.11 लाख विशेष जरूरतों वाले व्यक्तियों को वित्तीय सहायता दी गई है।
- किसी परिवार के आजीविका कमाने वाले सदस्य की मृत्यु पर एकबारगी वित्तीय सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत 2020-21 में 13,380 परिवारों की तुलना में 2021-22 में 1914 परिवारों को एकबारगी वित्तीय सहायता दी गई।

VII. महिला और बाल विकास विभाग

(I) आउटकम बजट 2021-22 में 17 कार्यक्रमों/योजनाओं को शामिल किया गया था जिनमें 91 आउटपुट/आउटकम संकेतक तय किए गए थे। विभाग के आउटपुट और आउटकम संकेतकों का विवरण इस प्रकार है:-

क	संकेतकों की कुल सख्या	91
ख	"लागू नहीं" संकेतकों की कुल संख्या	22
ग	मूल्यांकन के लिए संकेतकों की संख्या (क-ख)	69
i	संकेतकों की संख्या – "ऑन ट्रैक"	55 (80%)
ii	संकेतकों की संख्या– "ऑफ ट्रैक"	14 (20%)

(ii) प्रगति दर्शाने वाला पाई चार्ट

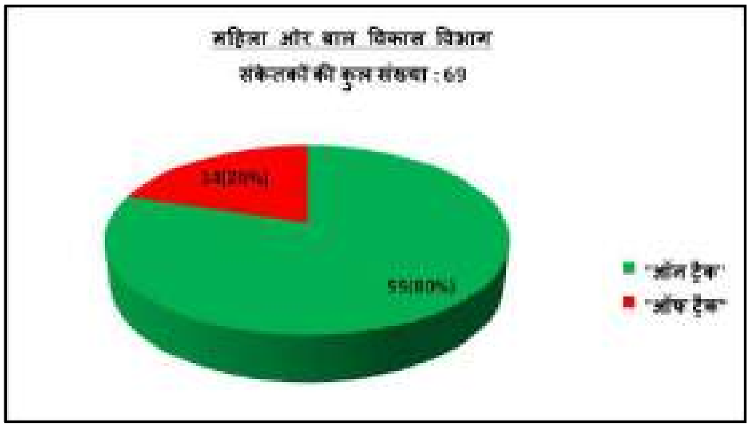

(ii) प्रमुख संकेतकों की स्थिति (दिसम्बर 2021 तक)

- 2021-22 में लगभग 3.10 लाख संकटग्रस्त महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता दी गई जबकि 2020-21 में ऐसी 2.81 लाख महिलाओं को वित्तीय सहायता दी गयी थी।
- लगभग 1600 गरीब विधवाओं को उनकी बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता (30,000/- रु.) दी गई।
- दिसंबर 2021 तक लाडली योजना के तहत 43,659 बालिकाओं का नामांकन (जन्म स्तर+स्कूल स्तर पर) किया गया। वर्ष की तीसरी तिमाही तक 16,505 परिपक्वता मामलों का भुगतान किया जा चुका है।
- लगभग 13.91 लाख बच्चे और गर्भवती/स्तनपान कराने वाली माताएं आईसीडीएस के तहत चल रहे 10,896 आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य सेवाओं और स्कूल पूर्व सेवाओं का लाभ उठा रही हैं।
- दिल्ली महिला आयोग के तहत 219 महिला पंचायत की स्थापना की गई

VIII. अजा/अजजा/अपिव कल्याण विभाग

(I) आउटकम बजट 2021-22 में 12 कार्यक्रम/योजनाएं शामिल की गई, जिनमें 41 आउटपुट/आउटकम संकेतक तय किए गए। विभाग के आउटपुट और आउटकम संकेतकों का विवरण है:-

क	संकेतकों की कुल सख्या	41
ख	"लागू नहीं" संकेतकों की कुल संख्या	14
ग	मूल्यांकन के लिए संकेतकों की संख्या (क-ख)	27
i	संकेतकों की संख्या – "ऑन ट्रैक"	12 (44%)
ii	संकेतकों की संख्या– "ऑफ ट्रैक"	15 (56%)

(ii) प्रगति दर्शाने वाला पाई चार्ट:

(ii) प्रमुख संकेतकों की स्थिति (दिसम्बर 2021 तक)

- दिसंबर 2021 तक 37,737 छात्र/छात्राओं को गत वर्ष की छात्रवृत्ति/मेरिट छात्रवृत्ति प्रदान की गई।
- अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यकों और अनाथ जैसे कमजोर वर्गों के लिए ईसापुर गांव में आवासीय विद्यालय में 836 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं।
- "जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना" के तहत दिसंबर 2021 तक 46 कोचिंग संस्थानों को पैनल में रखा गया है। इस योजना के तहत प्रतिस्पर्धी कोचिंग के लिए दिसंबर 2021 तक 12,297 छात्रों/छात्राओं का नामांकन किया गया।
- अनुसूचित जाति बस्तियों में सुधार कार्य के लिए दिसंबर 2021 तक 90 स्वीकृतियां जारी की गईं।

IX. खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग

(I) आउटकम बजट 2021-22 में 4 कार्यक्रम/योजनाएं शामिल की गई, जिनमें 19 आउटपुट/आउटकम संकेतक तय किए गए। विभाग के आउटपुट और आउटकम संकेतकों का विवरण है:-

क	संकेतकों की कुल सख्या	19
ख	"लागू नहीं" संकेतकों की कुल संख्या	8
ग	मूल्यांकन के लिए संकेतकों की संख्या (क-ख)	11
i	संकेतकों की संख्या – "ऑन ट्रैक"	07 (64%)
ii	संकेतकों की संख्या– "ऑफ ट्रैक"	04 (36%)

(ii) प्रगति दर्शाने वाला पाई चार्ट:

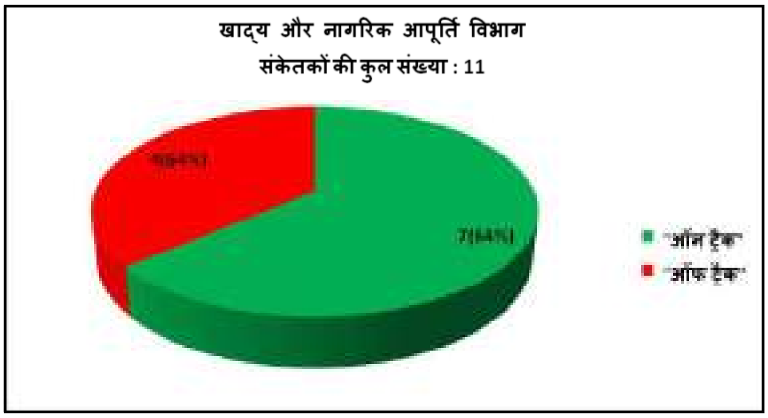

(ii) प्रमुख संकेतकों की स्थिति (दिसम्बर 2021 तक)

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत दिल्ली ने 72.78 लाख एनएफएस लाभार्थियों की अधिकतम सीमा हासिल कर ली है। परन्तु, दिसंबर 2021 तक हर महीने औसतन 68.94 लाख लाभार्थी राशन के लिए लाभान्वित हुए।
- 31.76 लाख गैर-पीडीएस लाभार्थियों को दिसंबर 2021 तक प्रवासी श्रमिकों और कमजोर लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर राशन दिया गया।
- अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के तहत लगभग 69,000 परिवारों को चीनी की पात्रता के साथ राशन दिया गया।
- वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) के माध्यम से दिसंबर 2021 तक औसतन 4.48 लाख गैर-दिल्ली लाभार्थियों को राशन दिया गया।

X. शहरी विकास विभाग और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड

(I) आउटकम बजट 2021-22 में 12 कार्यक्रम/योजनाएं शामिल की गई, जिनमें 66 आउटपुट/आउटकम संकेतक शामिल हैं। विभाग के आउटपुट और आउटकम संकेतकों का विवरण है:-

क	संकेतकों की कुल सख्या	66
ख	"लागू नहीं" संकेतकों की कुल संख्या	10
ग	मूल्यांकन के लिए संकेतकों की संख्या (क-ख)	56
i	संकेतकों की संख्या – "ऑन ट्रैक"	25 (45%)
ii	संकेतकों की संख्या– "ऑफ ट्रैक"	31 (55%)

(ii) प्रगति दर्शाने वाला पाई चार्ट

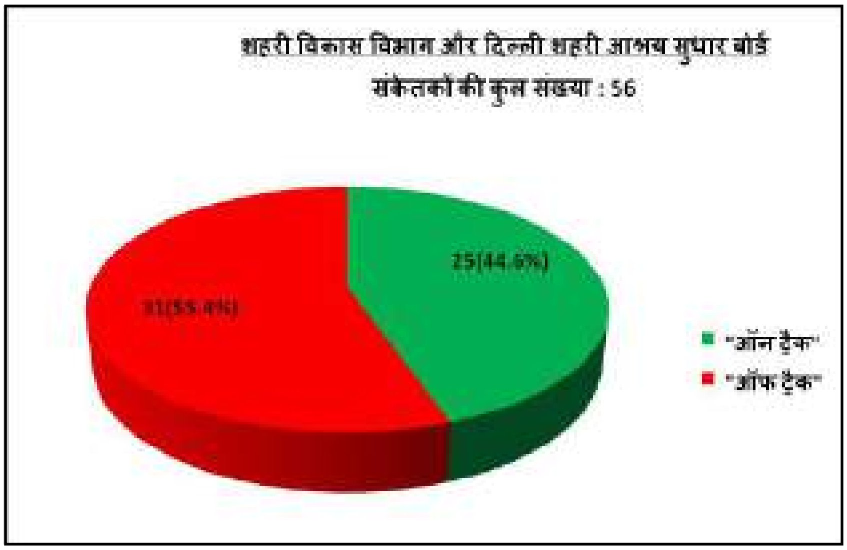

(ii) प्रमुख संकेतकों की स्थिति (दिसम्बर 2021 तक)

- कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बावजूद 'मुख्यमंत्री सड़क प्रोत्साहन योजना' के तहत 371 परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है।
- डूसिब 10 स्थानों पर अस्थायी रैन बसेरों के अतिरिक्त, 195 रैन बसेरों का संचालन और प्रबंधन कर रहा है। 195 रैन बसेरों की क्षमता सामान्य मौसम में 6941 और सर्दियों के दौरान 9100 है। हालांकि, कोविड महामारी की अवधि के दौरान सुरक्षित दूरी बनाए रखने का पालन सुनिश्चित किया गया था

फिर भी रैन बसेरों में प्रतिदिन औसत इस्तेमाल सामान्य मौसम में 71 % और सर्दियों के दौरान 78 % किया गया। रैन बसेरों में रहने वाले सभी सदस्यों के लिए दोनों वक्त के भोजन की व्यवस्था है।

- 628 जन सुविधा परिसरों (जिसमें 20,914 शौचालय सीटें शामिल हैं) का दिसंबर, 2021 तक सफलतापूर्वक रखरखाव किया गया।
- दिसंबर, 2021 तक 308 बस्ती विकास केंद्रों और 202 सामुदायिक भवनों का सफलतापूर्वक रखरखाव किया गया।

XI. दिल्ली जल बोर्ड

(I) आउटकम बजट 2021-22 में 11 कार्यक्रम/योजनाएं शामिल की गई, जिनमें 57 आउटपुट/आउटकम संकेतक शामिल हैं। विभाग के आउटपुट और आउटकम संकेतकों का विवरण है:-

क	संकेतकों की कुल सख्या	57
ख	"लागू नहीं" संकेतकों की कुल संख्या	1
ग	मूल्यांकन के लिए संकेतकों की संख्या (क-ख)	56
i	संकेतकों की संख्या – "ऑन ट्रैक"	35 (62.50%)
ii	संकेतकों की संख्या– "ऑफ ट्रैक"	21 (37.5%)

(ii) प्रगति दर्शाने वाला पाई चार्ट

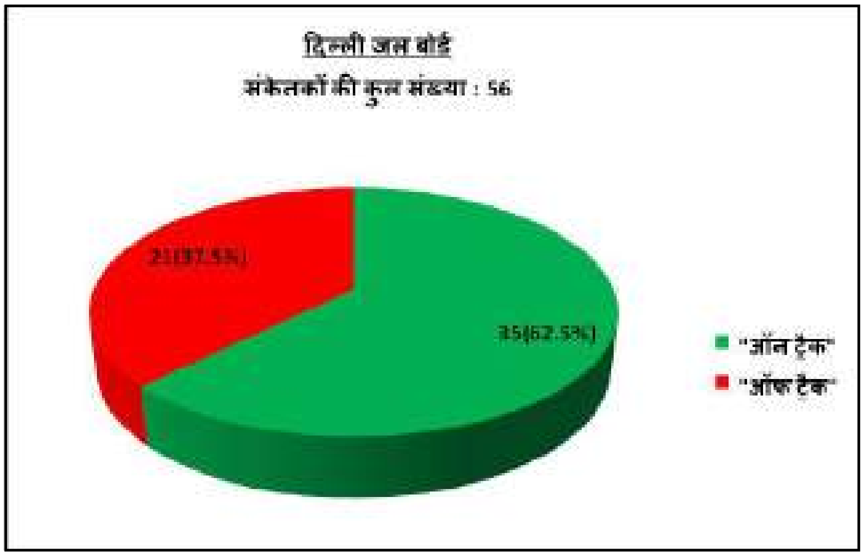

(ii) प्रमुख संकेतकों की स्थिति (दिसम्बर 2021 तक)

- दिसंबर, 2021 तक कुल 2955.60 किलोमीटर पुरानी/दोषपूर्ण पाइपलाइनों को बदल दिया गया है। परिणामस्वरूप, 4 एमजीडी पानी की बचत हुई।
- अनधिकृत कॉलोनियों में कुल 4855 किलोमीटर लंबी पानी की पाइप लाइन बिछाई गई है और पानी की आपूर्ति के लिए पानी के टैंकरों की संख्या कम करने के लिए दिसंबर, 2021 तक 1650 अनधिकृत कॉलोनियों को पानी की पाइप लाइनों से जोड़ा गया है।

- दिल्ली में 20 किलोलीटर पानी प्रति महीने नि:शुल्क आपूर्ति करने की योजना के अंतर्गत दिसम्बर 2021 तक, 6 लाख से अधिक उपभोक्ता लाभान्वित हुए। यह योजना अभी जारी है।
- दिसंबर, 2021 तक अनधिकृत कॉलोनियों में कुल 2991 किलोमीटर सीवर लाइन बिछाई गई है और 685 अनधिकृत कॉलोनियों को सीवरेज नेटवर्क से जोड़ा गया है।

XII. परिवहन विभाग

(I) आउटकम बजट 2021-22 में 12 कार्यक्रम/योजनाएं शामिल की गई, जिनमें 88 आउटपुट/आउटकम संकेतक तय किए गए। विभाग के आउटपुट और आउटकम संकेतकों का विवरण है:-

क	संकेतकों की कुल सख्या	88
ख	"लागू नहीं" संकेतकों की कुल संख्या	04
ग	मूल्यांकन के लिए संकेतकों की संख्या (क-ख)	84
i	संकेतकों की संख्या – "ऑन ट्रैक"	62 (74%)
ii	संकेतकों की संख्या– "ऑफ ट्रैक"	22 (26%)

(ii) प्रगति दर्शाने वाला पाई चार्ट:

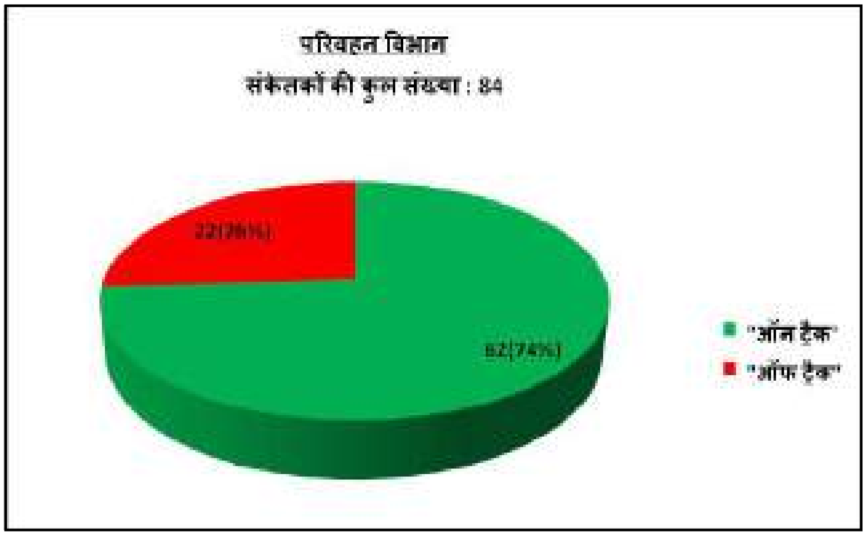

(ii) प्रमुख संकेतकों की स्थिति (दिसम्बर 2021 तक)

- सभी सार्वजनिक सेवाएं फेसलेस तरीके से उपलब्ध कराने के लिए परिवहन विभाग ने एक बड़ी पहल की है। दिसंबर 2021 तक परमिट संबंधी सेवा के लिए 82888 अनुरोध प्राप्त हुए।
- दिसंबर 2021 तक दिल्ली इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति के तहत 6,670 ई-दोपहिया और 12,136 ई-रिक्शा/ई-कार्ट पंजीकृत किए गए हैं और इस वर्ष के दौरान अब तक कुल 21,554 ई-वाहन पंजीकृत किए गए हैं।
- 28 बैटरी स्वैपिंग पॉइंट सेटअप और 8.2% नए वाहन पंजीकृत हैं जो ई-वाहन हैं जिसमें 4.2%

दोपहिया वाहन और 1.4% कारें दिसंबर 2021 तक पंजीकृत हैं। इसके साथ ही 6,123 वाहनों को राज्य ईवी फंड से सब्सिडी प्रदान की गई है।

- दिसंबर 2021 तक 377 पब्लिक चार्जिंग सेंटर, 170 स्लो चार्जिंग पॉइंट और 207 मॉडरेट/फास्ट चार्जिंग पॉइंट स्थापित किए गए हैं।
- जनता के बीच जागरूकता पैदा करने और समय-समय पर प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणन को नियंत्रित करने के लिए 971 पीयूसीसी केंद्र पीयूसीसी जारी करते हैं। 72.5 % दोपहिया वाहन और 74.6 % चार पहिया वाहन वैध पीयूसीसी के साथ चल रहे हैं जबकि पीयूसीसी रहित वाहनों के 28445 चालान काटे गए।
- दिल्ली में दिसंबर 2021 तक 11 स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक चालू हैं।
- 3760 डीटीसी बसों में से, बसों का औसत फ्लीट उपयोग प्रतिशत बढ़कर 83.18% हो गया, जबकि इसका लक्ष्य 86 % था। समय पर संचालित डीटीसी बसों का प्रतिशत बढ़कर 85.23 % हो गया जबकि इसका लक्ष्य 80 % था।
- 3082 क्लस्टर बसों में से, क्लस्टर बसों के औसत फ्लीट उपयोग का % बढ़कर 99.01% हो गया है, जबकि लक्ष्य 97 % है और क्लस्टर बसों का समय पर प्रदर्शन 75 % के लक्ष्य के मुकाबले बढ़कर 72.94 % हो गया है।
- डीटीसी और क्लस्टर बसों में क्रमशः 40 % और 35.21% गुलाबी पास प्रतिदिन जारी किए जाते हैं।
- डीटीसी और क्लस्टर बसों में क्रमशः 97.44% और 72.87% बसें दोनों शिफ्टों में मार्शलों के साथ संचालित हैं।
- दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन (0.851 किमी) पर त्रिलोकपुरी से मयूर विहार पॉकिट और नजफगढ़ लाइन का ढांसा बस स्टैंड (0.891 किमी) तक का कार्य पूरा किया गया और ये अनुभाग सार्वजनिक सेवाओं के लिए चालू किए गए।
- तीसरे चरण के पूरा होने के साथ, लगभग 291 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइनों का एक बड़ा नेटवर्क परिचालन में है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 211 मेट्रो स्टेशन शामिल हैं।
- दिसंबर 2021 तक DMRC चरण- IV के तहत लगभग 20% काम पूरा किया जा चुका है।

XIII. लोक निर्माण विभाग (सड़क और पुल)

(i) आउटकम बजट 2021-22 में 36 आउटपुट/आउटकम संकेतकों के साथ 17 कार्यक्रम/स्कीम शामिल की गई थी। विभाग के आउटपुट और आउटकम संकेतकों का ब्यौरा इस प्रकार है :-

क	संकेतकों की कुल सख्या	36
ख	“लागू नहीं” संकेतकों की कुल संख्या	02
ग	मूल्यांकन के लिए संकेतकों की संख्या (क-ख)	34
i	संकेतकों की संख्या – “ऑन ट्रैक”	24 (71%)
ii	संकेतकों की संख्या– “ऑफ ट्रैक”	10 (29%)

(ii) प्रगति दर्शाने वाला पाई चार्ट:

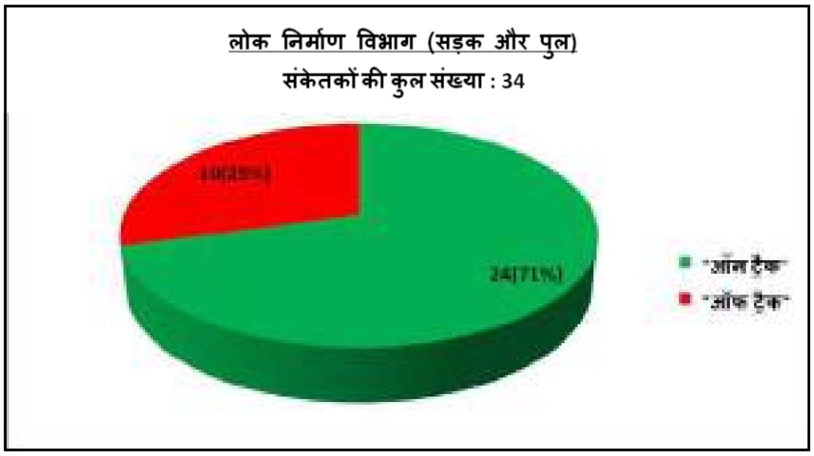

(ii) प्रमुख संकेतकों की स्थिति (दिसम्बर 2021 तक)

- आजादी के 75 वर्ष के समारोह के लिए दिसंबर 2021 तक पांच राष्ट्रीय ध्वज लगाए गए। जनवरी 2022 तक इन राष्ट्रीय ध्वजों की संख्या बढ़कर 75 हो गई है।
- दिसंबर 2021 तक विभिन्न विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में आम लोगों की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्थलों पर वर्ष 2021-22 में एक लाख 33 हजार सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, जबकि लक्ष्य एक लाख 49 हजार कैमरे लगाने का था।
- दिसंबर 2021 तक दो हजार नए वाईफाई हॉटस्पॉट लगाए गए और अब दिल्ली में संचालित वाईफाई हॉट स्पॉट की संख्या 10500 हो गई है।

- बसाईदारापुर में नजफगढ़ नाले पर पुल को चौड़ा करने का 94 % काम दिसंबर 2021 तक पूरा हो चुका है।
- नांगलोई में एन एच-10 पर नजफगढ़ नाले पर पुलों को चौड़ा करने का 67% कार्य दिसंबर 2021 तक पूरा हो गया है।
- (i) रामपुरा में एनएच-10, (ii) त्रिनगर/इंद्रलोक और (iii) कर्मपुरा में पुलों को चौड़ा करने का 94 % काम दिसंबर 2021 तक पूरा कर लिया गया है।
- आश्रम फ्लाईओवर से डीएनडी फ्लाईओवर तक फ्लाईओवर विस्तार का 40% काम दिसंबर 2021 तक पूरा हो चुका है।
- वजीराबाद और जगतपुर के बीच दो वाहन हाफ अंडरपास और आउटर रिंग रोड पर गांधी विहार के निकट सब-वे का 65% कार्य दिसंबर 2021 तक पूरा कर लिया गया है।
- आश्रम चौक पर अंडर पास बनाने का 90 % कार्य दिसंबर 2021 तक पूरा कर लिया गया है।
- दो फुटओवर ब्रिज का निर्माण कार्य दिसंबर 2021 तक पूरा हो चुका है।

XIV. विद्युत् विभाग

(I) आउटकम बजट 2021-22 में 61 आउटपुट/आउटकम संकेतकों के साथ 11 कार्यक्रम/स्कीम शामिल की गई थीं, जिनमें 34 महत्वपूर्ण संकेतक हैं। विभाग के आउटपुट और आउटकम संकेतकों का ब्योरा इस प्रकार है:

क	संकेतकों की कुल सख्या	61
ख	"लागू नहीं" संकेतकों की कुल संख्या	9
ग	मूल्यांकन के लिए संकेतकों की संख्या (क-ख)	52
i	संकेतकों की संख्या – "ऑन ट्रैक"	43 (83%)
ii	संकेतकों की संख्या– "ऑफ ट्रैक"	09 (17%)

(ii) प्रगति दर्शाने वाला पाई चार्ट:

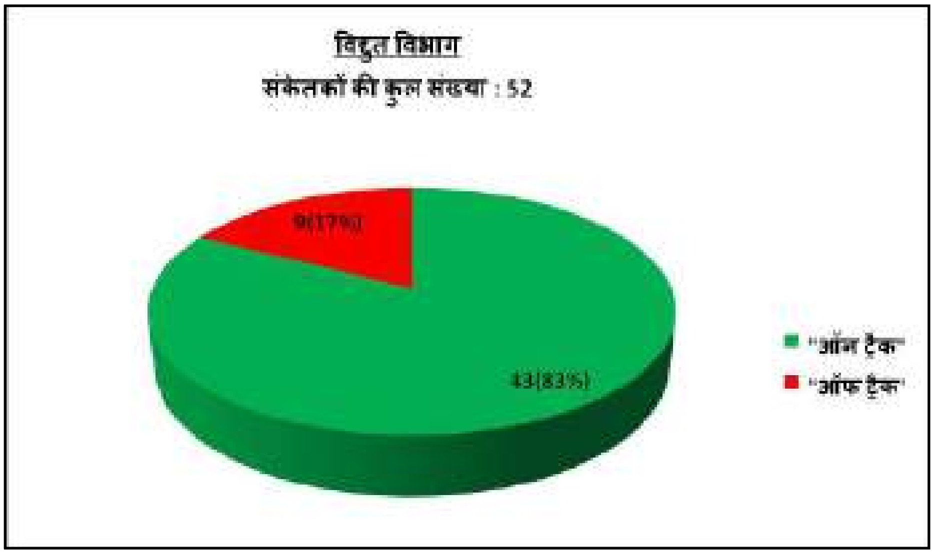

(ii) प्रमुख संकेतकों की स्थिति (दिसम्बर 2021 तक)

- 1150 संयंत्रों के लक्ष्य के सापेक्ष में दिसंबर 2021-22 तक सरकारी इमारतों पर 1160 रूफ टॉप सौर पीवी संयंत्रों को लगाया गया तथा निजी भवनों मे दिसंबर 2021 तक 4500 संयंत्रों के लक्ष्य के सापेक्ष में 4519 रूफ टॉप सौर पीवी संयंत्र लगाए गए।

- दिल्ली ने अप्रैल से दिसंबर 2021 के दौरान सफलता पूर्वक 7323 मेगावाट बिजली की पीक मांग पूरी की।
- दिसंबर 2021 तक एटीएंडसी क्षति 7.37% (बीआरपीएल), 7.88% (बीवाईपीएल) और 6.31% (टीपीडीडीएल) की थी।
- बिजली विभाग ने प्रतिमाह 200 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिलों पर शत- प्रतिशत सब्सिडी दी है। 201 से 400 यूनिट प्रतिमाह बिजली उपभोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 800 रुपए प्रतिमाह की सब्सिडी दी गई है। इससे दिसंबर 2021 तक कुल 54 लाख 20 हजार घरेलू बिजली उपभोक्ताओं में से 46 लाख 93 हजार यानि 86.60 % उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है।
- दिल्ली में दिसंबर 2021 तक 897.601 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए गए हैं, लक्ष्य 1825 मेगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करना था। इन संयंत्रों से दिसंबर 2021 तक 692.049 मेगा यूनिट सौर ऊर्जा सृजित हुई है जहां वार्षिक लक्ष्य 750 मेगा यूनिट उत्पादन का था।

XV. पर्यावरण और वन विभाग

(I) आउटकम बजट 2021-22 में 63 आउटपुट/आउटकम संकेतकों के साथ 15 कार्यक्रम/स्कीम शामिल की गई थी। विभाग के आउटपुट और आउटकम संकेतकों का ब्योरा इस प्रकार है:-

क	संकेतकों की कुल सख्या	63
ख	"लागू नहीं" संकेतकों की कुल संख्या	13
ग	मूल्यांकन के लिए संकेतकों की संख्या (क-ख)	50
i	संकेतकों की संख्या – "ऑन ट्रैक"	35 (70%)
ii	संकेतकों की संख्या– "ऑफ ट्रैक"	15 (30%)

(ii) प्रगति दर्शाने वाला पाई चार्ट

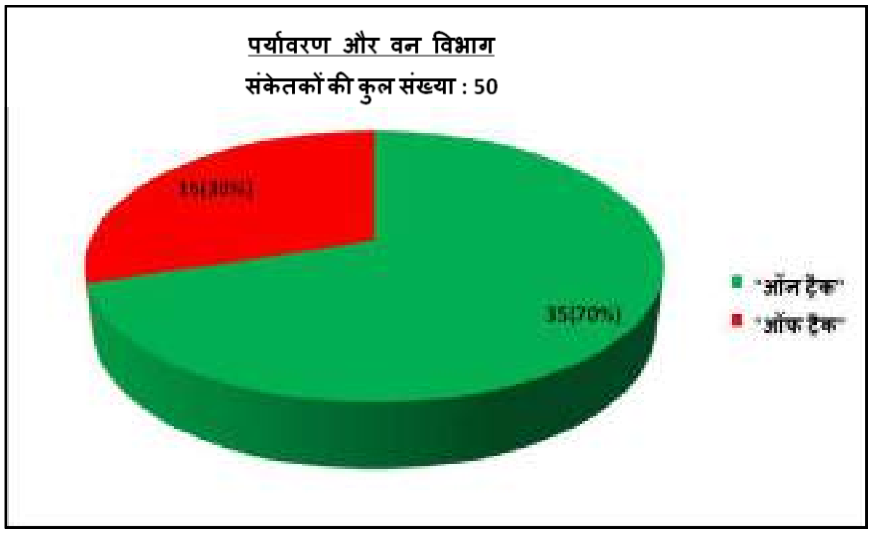

(ii) प्रमुख संकेतकों की स्थिति (दिसम्बर 2021 तक)

- सभी 26 परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र कार्य कर रहे हैं। 90 % आंकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं।
- उद्योगों, बिजली संयंत्रो, होटल इत्यादि से उत्सर्जन की निगरानी के लिए दिसंबर 2021 तक 176 स्टैक सैंपल का परीक्षण किया गया। 2021-22 की अवधि में वार्षिक लक्ष्य 700 सैंपल के परीक्षण का था। इनमें से शत- प्रतिशत नमूने निर्धारित मानकों पर खरे उतरे।

- दिसंबर 2021 तक एसटीपी, सीईटीपी, यमुना नदी, नालों और ईटीपी की निगरानी लिए STPs से 438 तरल नमूनों का परीक्षण किया गया। वार्षिक लक्ष्य 408 नमूनों का परीक्षण का था। इनमें से 52 % नमूने निर्धारित कसौटी पर खरे रहे। इसी प्रकार दिसंबर 2021 तक सीईटीपी से 206 तरल नमूनों का परीक्षण किया गया। वार्षिक लक्ष्य 156 नमूनों के परीक्षण का था। इनमें से 63.11 % नमूनों ने निर्धारित मानक पूरा किया।
- ईटीपी से 171 तरल नमूनों का परीक्षण दिसंबर 2021 तक किया गया। वार्षिक लक्ष्य 300 नमूनों के परीक्षण का था। इनमें से 90.64 % नमूने निर्धारित मानक पर खरे उतरे।
- दिसंबर 2021 तक प्रदूषण नियंत्रण नियमों और अधिनियमों की उल्लंघन की जांच के लिए 6460 उद्योगों का निरीक्षण किया गया। इनमें से 1778 उद्योगों को बंद करने का आदेश जारी किया गया। इनमें से 75 % इकाईयां 2021 तक बंद कर दी गई।
- जैव चिकित्सा कचरा प्रबंधन विनियम, 2016 के अंतर्गत दिसम्बर 2021 तक अनुमति के लिए 713 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 68.30% आवेदनों का निपटारा 30 दिन के अंदर कर दिया गया।
- ग्रीन दिल्ली ऐप के तहत प्रदूषणरोधी नियमों के उल्लंघन के लिए दिसंबर 2021 तक की गई 14980 शिकायतों में से 93 % का समाधान निर्धारित समय सीमा में कर दिया गया।
- 2021-22 के दौरान 2 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था, जबकि दिसंबर 2021 तक असोला भाटी वन्य जीव अभराण्य के बाहरी क्षेत्र में 2 लाख 11 हजार पौधे लगा दिए गए।
- दिसंबर 2021 तक वन क्षेत्र में 4 लाख 93 हजार पौधे लगाए गए, जबकि लक्ष्य वर्ष 2021-22 के दौरान 6 लाख पौधे लगाने का है।
- वर्ष 2021-22 के दौरान 6 शहरी वनों के विकास का लक्ष्य रखा गया है। दिसंबर 2021 तक पांच शहरी वनों के विकास का 60 % काम पूरा हो चुका था।
- विभागीय नर्सरियों से 4 लाख 20 हजार पौधों का निशुल्क वितरण दिसंबर 2021 तक किया गया। वार्षिक लक्ष्य चार लाख पौधों के वितरण का था।
- दिसंबर 2021 तक वनों में 493 हेक्टेयर हरित क्षेत्र विकसित किया गया। 2021-22 के दौरान लक्ष्य 600 हेक्टेयर हरित वन क्षेत्र विकास का है।

XVI. प्रशासनिक सुधार विभाग

(I) आउटकम बजट 2021-22 में 13 आउटपुट/आउटकम संकेतकों के साथ 3 कार्यक्रम/स्कीम शामिल की गई थी। विभाग के आउटपुट और आउटकम संकेतकों का ब्योरा इस प्रकार है:-

क	संकेतकों की कुल सख्या	13
ख	"लागू नहीं" संकेतकों की कुल संख्या	01
ग	मूल्यांकन के लिए संकेतकों की संख्या (क-ख)	12
i	संकेतकों की संख्या – "ऑन ट्रैक"	09 (75%)
ii	संकेतकों की संख्या– "ऑफ ट्रैक"	03 (25%)

(ii) प्रगति दर्शाने वाला पाई चार्ट:

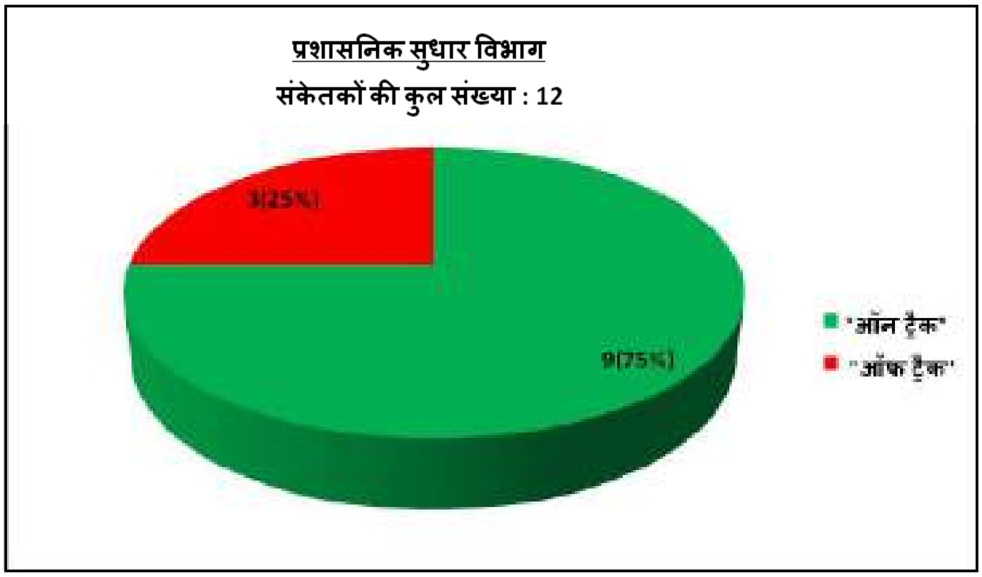

(ii) प्रमुख संकेतकों की स्थिति (दिसम्बर 2021 तक)

- 'द्वार तक जन सेवाओं की आपूर्ति' स्कीम के अंतर्गत दिसंबर 2021 तक 1,17,954 सेवाएं पूरी की गई। वर्ष 2020-21 में 77,678 सेवाओं की आपूर्ति हुई थी।
- पीजीएमएस- जन शिकायत' स्कीम के अंतर्गत मिली 94, 081 शिकायतों में से 81,989 शिकायतों का निपटारा दिसंबर 2021 तक कर दिया गया।
- दिसंबर 2021 तक 48,394 ई-आरटीआई में से 36,542 ई-आरटीआई का निपटान 30 दिनों के अंदर कर दिया गया।

XVII. आउटकम बजट से सीख और आगे का रास्ता

23. अध्यक्ष महोदय, दिल्ली का व्यापक आउटकम बजट बेजोड़ बजटीय पहल है जो योजनाओं और कार्यक्रमों की निगरानी की प्रक्रिया को बदल रहा है। यह न केवल आम जनता और हमारे विभागों के लिए एक उपकरण है, बल्कि किसी शोधकर्ता के लिए विभिन्न विभागों और उनके कार्यक्रमों के कामकाज का अध्ययन करने के लिए एक दस्तावेज भी है। यह माननीय मंत्रियों द्वारा समय-समय पर योजनाओं/कार्यक्रमों की प्रगति की निगरानी और मूल्यांकन के लिए एक तंत्र भी है। यह ऐसा दस्तावेज है जिसका देश भर के राज्यों द्वारा अनुकरण किया जा सकता है।

24. आउटकम बजट के संदर्भ में विभागों के प्रदर्शन की समीक्षा एक अतिरिक्त पहल है जो इस सरकार का एक अद्वितीय और साहसिक कदम है, जो वर्ष के अंत में मात्रात्मक और पारदर्शी तरीके से किए गए कार्यों का अपना मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। विभाग अब अधिक सक्रिय हो गए हैं और अधिक लक्ष्योन्मुख दृष्टिकोण में काम कर रहे हैं, जो बेहतर परिणाम देता है।

25. आउटकम बजट शासन प्रणाली का एक अभिन्न अंग बन गया है और सरकार को सभी विभागों को उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंक करने में मदद करता है।

26. आउटकम बजट 2022-23 तैयार करने का कार्य योजना विभाग द्वारा शुरू किए जाने की संभावना है और आउटकम बजट की एक प्रति योजना विभाग की वेबसाइट पर डालने के साथ सभी माननीय सदस्यों को भेजी जाएगी, जो वर्ष 2022-23 के लिए विभिन्न संकेतकों एवं लक्ष्यों की तुलना में वर्ष 2021-22 की उपलब्धियों को इसकी नियमित निगरानी के लिए प्रस्तुत करेगी।

योजना विभाग

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार